



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

No. 300]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2005/आषाढ़ 16, 1927

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2005/ASADHA 16, 1927

गृह मंत्रालय

(सी. एस. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 458(अ).—केन्द्रीय सरकार, बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम पर लागू होंगे और भारत तथा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई संधि को अधिसूचित करती है, जो निम्नानुसार है :—

“दंडित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणतंत्र की सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच करार

भारत गणतंत्र की सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी देश कहा गया है;

दंडित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की इच्छा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई है :

अनुच्छेद 1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजन के लिए :

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के उस निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दंड दिया गया हो;
- (ख) “ग्रहणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दंडित व्यक्ति को सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जाएगा अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दंड” से तात्पर्य किसी निश्चित समयावधि अथवा आजीवन कारावास के दंड अथवा आजादी से वंचित रखे जाने की उस कार्रवाई से है जिसका आदेश अपने दंड अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा दिया गया हो;

- (घ) "दंडित व्यक्ति" से तात्पर्य संविदाकारी देशों में फिलहाल लागू कानून के अंतर्गत स्थापित न्यायालयों सहित किसी दंड न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) "अंतरणकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जाएगा या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

### अनुच्छेद 2

#### सामान्य सिद्धांत

1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित व्यक्ति को सजा काटने के लिए दूसरे देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है। इस संबंध में वह इस करार के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश अथवा ग्रहणकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. अंतरण का अनुरोध, संविदाकार देश के कानून के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक हो अथवा उसकी ओर से कार्यवाई करने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविदाकार देश को आवेदन प्रस्तुत करके तथा उस संविदाकार देश की सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 3

#### अंतरण की शर्तें

1. इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
  - (क) वह व्यक्ति ग्रहणकर्ता देश का नागरिक हो;
  - (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया गया हो;
  - (ग) निर्णय अंतिम हो;
  - (घ) अंतरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई ज्ञान, विचारण अथवा कोई अन्य कार्यवाही लंबित न हो;
  - (ङ) अंतरण का अनुरोध प्राप्त होने के समय दंडित व्यक्ति के दंड के अभी कम से कम छः माह बाकी हों अथवा वह आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा हो;
  - (च) कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिस कृत्य अथवा गलती के लिए दंड दिया गया था, वे ग्रहणकर्ता देश में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि उस देश के भू-भाग में वे कृत्य किए जाते तो वे अपराध माने जाते;
  - (छ) दंडित व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सैन्य नियम के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया गया हो;
  - (ज) ग्रहणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;
  - (झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर संविदाकार देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति; और
  - (ञ) अंतरणकर्ता और ग्रहणकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो।
2. आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और ग्रहणकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

### अनुच्छेद 4

#### सूचना भेजने का दायित्व

1. यदि दंडित व्यक्ति इस समझौते के अंतर्गत, दंड देने वाले देश को अंतरण की अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो अंतरणकर्ता देश ग्रहणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा बशर्ते कि ग्रहणकर्ता अथवा अंतरणकर्ता देश द्वारा पहले से ही यह निर्णय किया जा चुका हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है :
  - (क) दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता जन्म तिथि एवं जन्म स्थान ;
  - (ख) ग्रहणकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
  - (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
  - (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारम्भ होने की तारीख;
  - (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;

- (च) दंडित व्यक्ति की चिकित्सा, सामाजिक या कोई अन्य रिपोर्ट जो उसके आवेदन पत्र का निपटान करने या उसके कारावास की प्रकृति का निर्णय करने के लिए संगत हो;
- (छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए ग्रहणकर्ता देश यह विनिर्दिष्ट करे कि यह उसके अंतरण की सम्भावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति का या अंतरणकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अनुरूप उसकी ओर से कार्य करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति का अनुरोध; और
- (झ) किसी विवाचन पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से ग्रहणकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा जब कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :

- (क) एक विवरण या दस्तावेज जिसमें यह उल्लेख हो कि दंडित व्यक्ति ग्रहणकर्ता देश का नागरिक है ;
- (ख) यह मानते हुए कि वे कृत्य अथवा चूकें ग्रहणकर्ता देश के कानून के अंतर्गत एक अपराध है या यदि उनके क्षेत्र में की जाती तो उन्हें अपराध माना जाता, ऐसे कृत्यों अथवा चूकों के लिए ग्रहणकर्ता देश के संबंधित कानून की एक प्रति जिसके कारण अंतरणकर्ता देश में सजा सुनायी गई हो;
- (ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण के बाद ग्रहणकर्ता देश में दंड की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण और साथ में यदि लागू हो तो, उसके अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दंडित व्यक्ति का अंतरण स्वीकार करने के लिए ग्रहणकर्ता देश की इच्छा और दंडित व्यक्ति के शेष बचे दंड का प्रबंध करने की वचनबद्धता; और
- (ङ) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश जरूरी समझे।

#### अनुच्छेद 5

##### अनुरोध एवं उत्तर

1. अंतरण संबंधी अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में, यदि कोई हो, लिखित में किए जाएंगे तथा ये राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से अनुरोध किए जाने वाले देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित होंगे। इन अनुरोधों के उत्तर इन्हीं चैनलों के माध्यम से दिए जाएंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनार्थ भारत के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकारी, गृह मंत्रालय होगा, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के सम्बन्ध में :

- (i) इंग्लैंड और वेल्स के संबंध में महामहिम की कारागार सेवा;
- (ii) स्कॉटलैंड के संबंध में स्कॉटिस कारागार सेवा; तथा
- (iii) उत्तरी आयरलैंड के संबंध में नार्दन आयरलैंड प्रिजन सर्विस होगी।

3. अनुरोधकर्ता देश अनुरोध करने वाले देश को तत्काल अपने इस निर्णय से अवगत कराएगा कि वह इस अंतरण के अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं।

#### अनुच्छेद 6

##### सहमति तथा उसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि वह इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा 1(i) के अनुसार अंतरण की सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी सहमति स्वैच्छापूर्वक और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ दे रहा है। ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून से अधिशासित होगी।

2. अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने का अवसर देगा कि सहमति इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है।

**अनुच्छेद 7****ग्रहणकर्ता देश पर अंतरण का प्रभाव**

1. ग्रहणकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के तहत किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के जरिए, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित हो, दंड का प्रवर्तन जारी रखेगा।
2. इस करार के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के अधधीन दंड का प्रवर्तन ग्रहणकर्ता देश के कानून द्वारा नियंत्रित होगा और केवल वही देश सभी उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

**अनुच्छेद 8****दंड का सतत प्रवर्तन**

1. ग्रहणकर्ता देश अंतरणकर्ता देश द्वारा यथानिर्धारित सजा के कानूनी स्वरूप और अवधि से बाध्यकारी होगा।
2. तथापि, यदि दिया गया दंड अपने स्वरूप अथवा अवधि अथवा दोनों ही की दृष्टियों से ग्रहणकर्ता देश के कानून से असंगत हो अथवा उसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सजा अथवा उपाय में परिवर्तित कर सकता है। जहां तक इसके स्वरूप तथा अवधि का संबंध है, सजा अथवा उपाय यथासंभव अंतरणकर्ता देश के फैसले में दी गई सजा के संगत होने चाहिए। तथापि इससे अंतरणकर्ता देश में दी गई सजा के स्वरूप अथवा अवधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुच्छेद 9****अंतरणकर्ता देश पर दंड पूरा होने का प्रभाव**

जब ग्रहणकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1(क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है तो ऐसी अधिसूचना का प्रभाव अंतरणकर्ता देश में उस दंड का पूरा होना माना जाएगा।

**अनुच्छेद 10****माफी, राजक्षमा अथवा दंड परिवर्तन**

- (1) फैसले की पुनरीक्षा के लिए किसी भी आवेदन के संबंध में केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय लेगा।
- (2) कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुसरण में माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकता है अथवा दंड में परिवर्तन कर सकता है।

**अनुच्छेद 11****दंड के प्रवर्तन की समाप्ति**

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो ग्रहणकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

**अनुच्छेद 12****दंड के प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. ग्रहणकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :
  - (क) जब दंड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो ; अथवा
  - (ख) यदि दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में ग्रहणकर्ता देश को चाहिए कि वह उसकी गिरफ्तारी की व्यवस्था करे और उसे ग्रहणकर्ता देश के संगत कानून के अंतर्गत अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराए;
2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो ग्रहणकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद 13****अभिवहन**

यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश इस करार के अनुसरण में अपने भूभाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा लेकिन वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से मना कर सकता है जो स्वयं उसका राष्ट्रिक हो। ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को ऐसे अंतरण के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

**अनुच्छेद 14****लागत**

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भूभाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर इस करार के प्रवर्तन में होने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किये जाएंगे। तथापि ग्रहणकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य साधन से कर सकता है।

**अनुच्छेद 15****प्रवर्तनीय भूभाग**

1. यह करार निम्न पर लागू होगा :

(क) भारत गणराज्य ; तथा

(ख) यूनाइटेड किंगडम के संबंध में, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, और आइल ऑफ मैन, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए किसी ऐसे भूभाग पर जिसके लिए यूनाइटेड किंगडम उत्तरदायी है और जिसके लिए करार को संविदाकारी देशों के बीच करार द्वारा विस्तारित किया गया है; और संविदाकारी देश के राज्य क्षेत्रों पर तदनुसार लागू माना जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुरूप किसी भूभाग में विस्तारित इस करार के प्रवर्तन को किसी भी संविदाकारी देश द्वारा दूसरे देश को राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजे गए छः माह के नोटिस की अवधि पूरी होने पर समाप्त किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 16****भाषा**

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोधकर्ता देश की राजभाषाओं की एक या अन्य भाषा में अनुदित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

**अनुच्छेद 17****लागू होने का दायरा**

यह करार इस के प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

**अनुच्छेद 18****संशोधन**

संविदाकारी देशों द्वारा सहमत इस करार के कोई संशोधन या आशोधन तभी प्रभावी होंगे जब राजनयिक टिप्पणियों द्वारा उनकी सम्पुष्टि हो जाए।

**अनुच्छेद 19****अंतिम प्रावधान**

1. यह करार, अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखित दस्तावेजों के परस्पर, विनिमय की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. यह करार उस तारीख से छः माह तक लागू रहेगा जिस तारीख को कोई भी संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को इसे समाप्त करने के बारे में लिखित सूचना देगा।

3. किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उस दंडित व्यक्ति के दंडों प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिसे इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में दिनांक 18 फरवरी, 2005 को हिन्दी और अंग्रेजी की दो प्रतियों में तैयार किया गया है।

भारत गणतंत्र की  
सरकार की ओर से

शिवराज वि. पाटिल  
गृह मंत्री

ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी  
आयरलैंड की यूनाइटेड  
किंगडम की सरकार की ओर से

जैक स्ट्रा.  
विदेश एवं राष्ट्रकुल मामलों के विदेश सचिव"

[ फा. सं. 17011/2/04-पी. आर.]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

203668/05-2

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2005

**G.S.R. 458(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and notifies the text of the treaty entered into between India and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as follows :—

**“Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the transfer of sentenced persons**

The Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to as the Contracting States;

**Desiring** to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

**Considering** that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

**Have agreed** as follows :

**ARTICLE 1****Definitions**

For the purpose of this Agreement :

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “receiving State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) “transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

**ARTICLE 2****General principles**

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.

**ARTICLE 3****Conditions for transfer**

- 1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions :
  - (a) the person is a national of the receiving State;
  - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
  - (c) the judgment is final;

- (d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
- (e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
- (f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

#### ARTICLE 4

##### Obligation to furnish information

1. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer :

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
- (b) his address, if any, in the receiving State;
- (c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
- (h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
- (i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer :

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions, on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his transfer;

- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

#### ARTICLE 5

##### Requests and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in relation to India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, shall be :

- (i) Her Majesty's Prison Service in relation to England and Wales;
- (ii) The Scottish Prison Service in relation to Scotland; and
- (iii) The Northern Ireland Prison Service in relation to Northern Ireland.

3. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

#### ARTICLE 6

##### Consent and its verification

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.

2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

#### ARTICLE 7

##### Effect of transfer for the receiving State

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

#### ARTICLE 8

##### Continued enforcement of sentence

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.

2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

#### ARTICLE 9

##### Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

#### ARTICLE 10

##### Pardon, amnesty or commutation and review of judgment

- (1) The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.
- (2) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.



**ARTICLE 11****Termination of enforcement of sentence**

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

**ARTICLE 12****Information on enforcement of sentence**

1. The receiving State shall notify the transferring State :

- (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
- (b) if the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State should make arrangements for his/her arrest and make him/her liable for committing an offence under the relevant law of the receiving State;

2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

**ARTICLE 13****Transit**

If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

**ARTICLE 14****Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

**ARTICLE 15****Territorial application**

1. This Agreement shall apply;

- (a) to the Republic of India, and
- (b) in relation to the United Kingdom, to Great Britain and Northern Ireland, and to the Isle of Man, and any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which the Agreement shall have been extended by agreement between the Contracting States;

and references to the territory of a Contracting State shall be construed accordingly.

2. The Application of this Agreement to any territory, in respect of which extension has been made in accordance with paragraph 1 of this Article, may be terminated upon expiry of six months' notice given by either Contracting State to the other through the diplomatic channels.

**ARTICLE 16****Language**

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language or one of the official languages of the requesting State.

**ARTICLE 17****Scope of application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

20360/05-3

**ARTICLE 18****Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes.

**ARTICLE 19****Final provisions**

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.

2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.

3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at New Delhi on the 18th day of February, 2005, in the Hindi and English languages, all texts being equally authentic.

For the Government of  
the Republic of India:

Sd/-

Shivraj V. Patil.

Home Minister

For the Government of the United Kingdom of  
Great Britain and Northern Ireland:

Sd/-

Jack Straw

Secretary of State for Foreign and  
Commonwealth Affairs

[F. No. 17011/2/2004-PR]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.